

प्रेषक,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र०।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: /पीए-सीआरडी/2009

दिनांक: ०५, सितम्बर, 2009

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित योजनाओं के एम०आई०एस० का संचालन जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से कराये जाने विषयक।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं से संबंधित कतिपय कार्य जैसे-फोटोग्राफी, एम०आई०एस० कार्यों की डाटा इन्ट्री/एम०आई०एस० अपडेशन, मस्टररोल, जाब-कार्ड फीडिंग आदि कार्यों को नेशनल ई-गवर्ननेन्स प्लान के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे 17909 जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। इस प्रक्रिया से नरेगा के उपरोक्त कार्य आसानी से ग्राम पंचायतों के समीप कराये जा सकते हैं।

अपने अधीन कार्यरत कार्यक्रम अधिकारीगण/खण्ड विकास अधिकारीगण जिन्हें नरेगा में विकास खण्ड स्तर पर प्रमुख दायित्व सौंपे गए हैं, को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि नरेगा योजना के एम०आई०एस० संचालन विषयक कार्य व अन्य योजनाओं में एम०आई०एस० अपडेशन का कार्य इन जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जा सकता है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 466/पीए-सीआरडी/09 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र०शासन।
- 2- स्टेट को-ऑर्डिनेटर, सेन्टर फार ई-गवर्ननेन्स, उ०प्र०।
- 3- श्री गोपेश तिवारी, आई०एल०एफ०एस०, नेशनल लेविल सर्विस एजेन्सी, लखनऊ।
- 4- जनसेवा केन्द्र से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश के सर्विस सेन्टर एजेन्सीज।

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।